जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

चूरू

Rashtradoot

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 18 संख्याः 18 प्रभात चूरू, रविवार 17 मई, 2026 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

क्या राहुल गांधी ने अपनी रीति-नीति बदली है?

क्या इस बदली शैली का असर अब कर्नाटक में भी दिखेगा?

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 मई। केरल के बाद कांग्रेस का फोकस अब कर्नाटक की ओर स्थानांतरित होने वाला है, जहाँ लंबे समय से नेतृत्व का मुद्दा सुलझाए जाने का इंतज़ार है।

इसे पिछले कई महीनों से टाला जा रहा है, कभी चुनाव के नाम पर, कभी कोई अन्य बहाना लेकर, जो भी नेतृत्व के दिमाग में आता है।

दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार डी.के. शिवकुमार के बीच सत्ता संघर्ष के बीच, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कथित रूप से मुख्यमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार के रूप में सामने आए हैं।

- पहले राहुल पार्टी में शांति बनाए रखने की इच्छा से शायद सबको सब तरह के वादे करते थे और इससे अन्ततोगत्वा कोई भी खुश नहीं रहता था व राहुल की छवि भी ढुलमुल नेता की होती जा रही थी।
- केरल में पहली बार, राहुल ने वेणुगोपाल के दबाव को नकारा तथा सतीशन को मु.मंत्री बनाया, जनता का उम्मीदवार मानते हुए।
- कर्नाटक में भी मु.मंत्री सिद्धारमैया का तथाकथित ढाई साल का कार्यकाल पूरा होने पर डीके शिवकुमार को मु.मंत्री पद देने का वादा था, क्या वादा पूरा करेंगे, राहुल? यह मामला अभी तक टलता रहा है, कभी कई राज्यों के चुनाव (बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, केरल आदि) के बहाने से।
- पर, अब कर्नाटक का मसला टलने की स्थिति में नहीं है और अब लग रहा है, अपनी बात रखने के लिए राहुल वादा निभाएंगे?
- वर्तमान मु.मंत्री सिद्धारमैया की मंत्रिमंडल के विस्तार की इजाज़त की अर्ज़ी अस्वीकार कर डीके शिवकुमार को कमान सौंपेगे।

घटनाक्रम के इस बदलाव को दर्शाने वाले पोस्टर भी नज़र आने लगे हैं।

लेकिन सूत्रों का कहना है कि यह परिदृश्य थोड़ा दूरगामी है।

सिद्धारमैया अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करना चाहते हैं। वे कैबिनेट फेरबदल की अनुमति चाहते हैं ताकि अपनी स्थिति मजबूत कर सकें और सत्ता में शीर्ष पर होने का आभास दे सकें।

डी.के. शिवकुमार से यह वादा किया गया था कि सिद्धारमैया के ढाई साल पूरे होने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा।

लेकिन वे अब भी प्रतीक्षा में हैं और आशा कर रहे हैं, पर नेतृत्व की ओर से कोई संदेश नहीं आया है।

सवाल यह उठता है कि राहुल ऐसे वादे और प्रतिबद्धताएं क्यों करते हैं, जिन्हें वे पूरा नहीं कर सकते? ऐसा लगता है कि यह उनके लिए आदत बन गया है।

कई राज्यों में कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई और सत्ता संघर्ष चल रहा है, जो कांग्रेस की पहचान बन गई है और अब कर्नाटक इस संघर्ष का नवीनतम मंच बनने जा रहा है।

'पंजाब में निगम चुनाव बैलेट पेपर से होंगे'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 मई। पंजाब में नगर निगम चुनावों की घोषणा के साथ ही, मतपत्र के उपयोग को लेकर तीव्र राजनीतिक बहस शुरू हो गई है।

चुनाव आयोग की पंजाब इकाई ने कहा है कि नगर निगम चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की बजाय, मतपत्र के माध्यम से होंगे, जिस पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने तुरंत विरोध जताया।

पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल ने राज्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की और मांग की कि चुनाव ईवीएम के माध्यम से कराए जाएँ, जैसा कि पहले की प्रथाओं में होता रहा है।

- पंजाब के चुनाव आयोग के इस आदेश से राज्य में बहस छिड़ गई है। भाजपा ने इस आदेश का कड़ा विरोध किया है।

भाजपा नेता का आरोप है कि आम आदमी पार्टी सरकार संभावित हार के डर से मतपत्र प्रणाली लागू कर रही है, ताकि मतगणना के दौरान वोटों में हेर-

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जून के मध्य में भाजपा की केन्द्रीय सरकार व संगठन में भारी फेरबदल?

मोदी सरकार के मंत्रिमंडल की 21 मई की बैठक में इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा होगी

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 मई। कभी भी पैरों तले जमीन न छोड़ने वाले संगठन के रूप में विख्यात भाजपा पार्टी के नेतृत्व ने, पश्चिम बंगाल में अपनी शानदार जीत के तुरंत बाद, संगठन और सरकार दोनों के पुनर्गठन का कार्य शुरू कर दिया है।

केन्द्र सरकार में कैबिनेट का फेरबदल लंबित था, क्योंकि एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल में 9 जून 2024 को शपथ लेने के बाद कैबिनेट का कोई विस्तार या फेरबदल नहीं हुआ था। इसी समय, नए भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन अपनी नई टीम की घोषणा करने वाले हैं। इस विषय पर प्रारंभिक चर्चा 21 मई को होने वाली केन्द्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में होने की संभावना है।

केन्द्रीय कैबिनेट में नए शामिल होने वाले चेहरों में उन राज्यों के प्रतिनिधि हो सकते हैं, जहाँ अगले विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और पंजाब। साथ ही, कुछ अनुभवी मंत्रियों को विशेष रुप से चुनावाधीन राज्यों में संगठनात्मक जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं।

अटकलें हैं कि केन्द्रीय कैबिनेट का विस्तार जून के दूसरे सप्ताह में होगा, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दूसरे वर्ष की समाप्ति से पहले या तुरंत बाद। युवा और महिलाओं को केन्द्रीय कैबिनेट में जगह मिलने की संभावना है। भाजपा नेतृत्व पश्चिम बंगाल को पुरस्कृत करने की योजना बना रहा है,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- मंत्रिमंडल में उन राज्यों के प्रतिनिधियों को स्थान मिलेगा, जहाँ 2027 में चुनाव होंगे, जैसे उत्तर प्रदेश व पंजाब।
- युवा नेता व महिलाओं को मंत्रिमंडल में नव नियुक्तियाँ मिल सकती हैं। साथ ही पार्टी तेलंगाना को भी महत्व देगी, क्योंकि तेलंगाना में अभी तक भाजपा को ज्यादा सफलता नहीं मिली है। उदाहरण के लिए केके अरूणा का नाम जोरों से चल रहा है महिला कोटा में, मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए।
- यह भी माना जा रहा है कि राघव चड्ढा को भी संगठन में भारी पद मिल सकता है, पंजाब में चुनाव की दृष्टि से।

'अगर आप अपना फोन नहीं देंगे तो वो बंदूक निकाल लेंगे'

प्रैस ब्रीफिंग के दौरान पत्रकार पर गरम हुए रूस के विदेश मंत्री लावरोव

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 मई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में अपनी यात्रा के दौरान रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का मीडिया के साथ एक तनावपूर्ण पल वायरल हो गया, जब उन्होंने एक पत्रकार को मीडिया ब्रीफिंग के दौरान चेतावनी दी कि अगर व्यवधान जारी रहा तो सुरक्षा कर्मी "बंदूक निकाल सकते हैं।"

मीडिया ब्रीफिंग के दौरान एक पत्रकार, जो कथित तौर पर फोन पर बात कर रहा था, ने बार-बार व्यवधान डाला। इस लगातार व्यवधान के कारण लावरोव ने ब्रेक लिया और सुरक्षा अधिकारियों से हस्तक्षेप करने को कहा।

इस दौरान लावरोव ने कहा, "क्या आप हमें अकेला छोड़ सकते हैं? या तो आप खुद या आपका फोन। इसके बाद उन्होंने ब्रीफिंग फिर से शुरू की।

लेकिन कुछ ही क्षण बाद व्यवधान फिर हुआ, जिससे रूस के विदेश मंत्री ने कड़ा रुख अपनाया।

उन्होंने कहा, "क्या आप हमें छोड़ सकते हैं? मैं मज़ाक नहीं कर रहा। अगर आप अपना फोन नहीं देंगे, तो वे बंदूक निकाल लेंगे।"

- सर्गेई लावरोव की प्रैस ब्रीफिंग के दौरान एक पत्रकार तेज आवाज़ में फोन पर बात कर रहा था, लावरोव ने तीन बार उसे टोका, अंत में वे भड़क गए।
- रूसी भाषा में पत्रकारों से वार्ता कर रहे लावरोव ने तीन बार अंग्रेजी भाषा में उसे चेतवानी दी थी या आप चुप रहें या अपना फोन बंद करें। पर, थोड़ी देर बाद उक्त पत्रकार ने पुनः फोन पर बात की तो लावरोव भड़क गए और बोले, मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, अगर आप फोन बंद नहीं करते है तो ये (सुरक्षाकर्मी) गन निकाल लेंगे।
- ज्ञातव्य है कि रूस के विदेश मंत्री नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आए हैं।

लावरोव भारत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए थे और इस दौरान उन्होंने भारतीय नेताओं के साथ कई उच्च-स्तरीय बैठकें भी कीं।

उन्होंने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ, चल रहे अंतरराष्ट्रीय संघर्षों, जिनमें यूक्रेन और पश्चिम एशिया की परिस्थितियाँ भी शामिल हैं, पर चर्चा की।

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, लावरोव ने प्रधानमंत्री को भारत-रूस सहयोग में हुए विकास के बारे में अवगत कराया, जो दिसंबर 2025 में हुई 23वीं

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'पाक तय करे, भूगोल का हिस्सा बनेगा या इतिहास का'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 मई। इस्लामाबाद को कड़ी सैन्य चेतावनी देते हुए, सेनाध्यक्ष जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने शनिवार को कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को आश्रय देना, और भारत के खिलाफ गतिविधियाँ जारी रखता है, तो उसे यह "निर्णय लेना होगा कि वह भूगोल का हिस्सा बनना चाहता है या इतिहास का।"

- आर्मी चीफ उपेन्द्रनाथ द्विवेदी ने पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी देते हुए, भारत विरोधी आतंकी गतिविधियाँ बंद करने को कहा।

दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में 'यूनिफॉर्म अनवील्ड' द्वारा आयोजित एक इंटरैक्टिव सत्र में, जब उनसे पूछा गया कि अगर पिछले साल के ऑपरेशन सिंदूर की परिस्थितियाँ फिर से उत्पन्न होती हैं, तो भारतीय सेना कैसे प्रतिक्रिया

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नीट पेपर लीक में पुणे की बॉटनी प्रोफेसर दिल्ली से गिरफ्तार हुई

उक्त प्रोफेसर मनीषा गुरुनाथ मंडहरे को एनटीए ने बतौर एक्सपर्ट नियुक्ति दी थी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 मई। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आज बताया कि पुणे की वनस्पति विज्ञान (बॉटनी) की एक महिला शिक्षक को दिल्ली में नीट-यूजी बायोलॉजी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिससे गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या नौ हो गई है।

सीबीआई ने बताया कि पूछताछ किये जाने के बाद वनस्पति विज्ञान की शिक्षक, मनीषा गुरुनाथ मंडहरे, को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया।

सीबीआई ने बताया कि उन्होंने नैशनल टैस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त होने के बाद, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (अंडरग्रेजुएट) प्रक्रिया में काम किया था।

अप्रैल में, उन्होंने पुणे की एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे, जो पहली ही गिरफ्तार हो चुकी हैं, के माध्यम से नीट उम्मीदवारों से संपर्क किया और अपने घर पर इन छात्रों को कोचिंग क्लास दी।

सीबीआई के अनुसार, उन्होंने कथित तौर पर बॉटनी और जूलॉजी के महत्वपूर्ण सवालों को छात्रों को बताकर उन्हें नोटबुक में लिखने और अपनी किताबों में मार्क करने को कहा। जांच एजेन्सी ने बताया कि उनमें से अधिकांश सवाल नीट-यूजी की वास्तविक परीक्षा (3 मई को हुई) से मेल खा रहे थे।

- सीबीआई मनीषा गुरुनाथ मंडहरे से पूछताछ कर रही है। पता चला है कि उसने अप्रैल में एक अन्य आरोपी पुणे की मनीषा वाघमारे के जरिए नीट अभ्यर्थियों से संपर्क किया था और उन्हें अपने घर पर कोचिंग दे रही थी।
- उसने अभ्यर्थियों को बॉटनी व ज़ूलॉजी के वे प्रश्न लीक किए जो 3 मई के पेपर में आए थे।
- सीबीआई ने गत 24 घंटे में देश भर में 6 जगहों पर रेड की, कई दस्तावेज, लैपटॉप, मोबाइल फोन आदि जब्त किए। अब तक दिल्ली, जयपुर, गुडगाँव, नासिक, पुणे व अहिल्या नगर से 9 आरोपी पकड़े जा चुके हैं।

सीबीआई ने पिछले 24 घंटों में देशभर के छह स्थानों पर छापेमारी भी की और आपत्तिजनक दस्तावेज़, लैपटॉप, बैंक स्टेटमेंट और मोबाइल फोन जब्त किए। जब्त की गई वस्तुओं का विस्तृत विश्लेषण किया जा रहा है।

अब तक गिरफ्तार नौ आरोपी दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर के निवासी हैं। इनमें से पांच सात दिन के लिये पुलिस हिरासत में हैं; पुणे से गिरफ्तार दो आरोपियों को दिल्ली लाया जा रहा है। शेष से पूछताछ की जा रही है।

ज्यादा बच्चे पैदा करने पर ईनाम देंगे चन्द्रबाबू

आंध्र प्रदेश, 16 मई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने आज राज्य में घटती जनसंख्या दर को रोकने के लिए बड़ा ऐलान किया। श्रीकाकुलम जिले के नरसन्नापेटा में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान नायडू ने कहा कि तीसरे बच्चे के जन्म पर परिवार को 30 हजार रुपये और चौथे बच्चे पर 40 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरकार अगले एक महीने में इस योजना का विस्तृत खाका जारी करेगी।

- कभी जनसंख्या नियंत्रण के समर्थक रहे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश में घटती जन्मदर पर चिंता जताई और घोषणा की कि तीसरे बच्चे के जन्म पर 30 हजार और चौथे पर 40 हजार रु. दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने यह घोषणा "स्वर्ण आंध्र-स्वच्छ आंध्र" कार्यक्रम के दौरान की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देने की दिशा में काम करेगी।

नायडू ने कहा, मैंने नया फैसला लिया है। तीसरे बच्चे के जन्म पर 30 हजार रुपये और चौथे बच्चे पर 40 हजार रुपये दिए जाएंगे। क्या यह सही फैसला नहीं है?

दिलचस्प बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू पहले जनसंख्या नियंत्रण के समर्थक माने जाते थे। लेकिन अब उन्होंने कहा कि समय बदल चुका है और समाज को जन्म दर बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना होगा।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अदालती आदेश की अवहेलना पर जयपुर कलैक्टर को अवमानना नोटिस

जयपुर, 16 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद अतिक्रमण से जुड़े मामले में अभ्यावेदन तय नहीं करने पर जयपुर कलेक्टर संदेश नायक को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने ये आदेश लक्ष्मण सिंह नरूका की ओर से दायर अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

- हाई कोर्ट ने फागी के गाँव में आम रास्ते पर अतिक्रमण के बारे में अभ्यावेदन लेकर 3 सप्ताह में विधि सम्मत कार्यवाही के लिए कहा था।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भाजपा अपनी विश्वसनीयता स्थापित करने में जुटी बंगाल में

एक तरफ तो हाऊस ऑफ टाटा से पुनः बंगाल में लौटने की गंभीरता से बात चलाई जा रही है

अंजन रॉय ----
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 मई। बंगाल में हाल ही में निर्वाचित भाजपा सरकार ने अपनी विश्वसनीयता साबित करने के लिए राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में तेज़ी से कई कदम उठाए हैं।

नये प्रशासन ने कड़े आदेश जारी किए हैं कि "कट मनी" की किसी भी मांग पर सख्ती से कार्यवाही की जाएगी, सड़कों पर कोई धार्मिक प्रार्थना नहीं होगी, तथा अन्य कई और नियमों के साथ -साथ, धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर के उपयोग पर रोक लगनी चाहिए।

राज्य में टाटा घराने की फिर से एंट्री को लेकर व्यापक उम्मीदें हैं। पुनर्निर्माण को कुछ व्यवस्थित करने की कोशिश में अनधिकृत इमारतों की एक श्रृंखला को ध्वस्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने ममता बनर्जी के भतीजे पर कड़ा रुख अपनाया और अभिषेक बनर्जी की फर्मों की अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया।

ममता बनर्जी के भतीजे, अभिषेक बनर्जी के निर्वाचन क्षेत्र में जाकर, अधिकारी ने मतदाताओं से स्वतंत्र रूप से अपना मतदान करने की अपील की। चुनाव आयोग ने फाल्टा निर्वाचन क्षेत्र में 21 मई को पुन: मतदान घोषित किया है।

अधिकारी ने फाल्टा के लोगों से क्षेत्र के लिए कई नई योजनाओं का वादा किया। उल्लेखनीय है कि लेफ्ट सरकार ने फाल्टा में बंगाल का पहला फ्री ट्रेड ज़ोन स्थापित किया था। लेकिन, अब यह एफ.ई. ज़ैड़ बुरी तरह से बीमारु हालत में है और ज्यादातर बंद हो चुका है। तृणमूल कांग्रेस ने इस निर्वाचन क्षेत्र पर सबसे अधिक दखल दिया था।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने फाल्टा क्षेत्र में मतदान रद्द कर दिया, क्योंकि ई.वी.एम. में छेड़छाड़ हुई थी। अधिकांश बूथों में भाजपा का बटन टेप से चिपका हुआ पाया गया।

अभिषेक बनर्जी ने डायमंड हार्बर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सात लाख वोट के अंतर से जीत का देश भर में रिकॉर्ड बनाया था। मुख्यमंत्री अधिकारी ने बनर्जी के करीबी सहयोगी जहाँगीर खान को चेतावनी दी थी कि किसी भी अवैध कार्रवाई से सख्ती से निपटाया जाएगा।

- दूसरी और मु.मंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को निलंबित करने के आदेश दिए, आर.जी. कर हॉस्पिटल एवं मैडिकल कॉलेज में एक युवा डॉक्टर के साथ बलात्कार व हत्या के मामले में पूर्ण निष्ठा से काम नहीं करने के आरोप में।
- तथा मु.मंत्री ने ये आदेश भी दिए कि सड़कों पर नमाज़ पढ़ने की प्रवृति तथा लाउड स्पीकर के धार्मिक स्थानों पर उपयोग को प्रतिबंधित करने के प्रयास होंगे।
- साथ ही ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के चुनाव क्षेत्र, डायमंड हार्बर में उनके सबसे नज़दीकी व शाबाशी प्राप्त समर्थक जहाँगीर खान को भी सार्वजनिक चेतावनी देकर निष्क्रिय करना इस बात को स्थापित करने का प्रयास है कि सरकार बदल गई है।

खान ने क्षेत्र के मतदाताओं को मतदान के लिए बाहर जाने पर गंभीर परिणामों की धमकी दी थी। खान और उनके गुंडों ने लोगों के घरों में प्रवेश कर उन्हें धमकाया; कई लोगों को बलात्कार और हत्या की धमकी दी गई थी।

एक बहुत महत्वपूर्ण कदम के रूप में, विवादास्पद आर.जी. कर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में हुए बलात्कार और हत्या मामले में तीन आई.पी.एस.अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया गया। नए मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने आज कोलकाता में सस्पैंशन का आदेश दिया और इसकी घोषणा की।

ज्ञातव्य है कि एक युवा महिला डॉक्टर को राज्य के आर.जी. कर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)